MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned at five minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock,

MR DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 2011-12

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHARATSINH SOLANKI): Mr Deputy Chairman, Sir, I lay on the Tablea statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 2011-12.

GOVERNMENT BILLS

The Citizenship (Amendment) Bill, 2011

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Mr Deputy Chairman, on behalf of my senior colleague, Shri P. Chidambaram, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA):): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to submit for your kind consideration that it is a very important Bill. It deserves the presence of the Cabinet Minister. Somewhat unfortunate that the Cabinet is not here to hear this debate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Cabinet Minister has written a letter that she was going out of the country; and her colleague the Minister of State will move the Bill. She has taken permission from the Chair.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। प्रसार भारती के कार्यक्रमों से भारत के ही करोड़ों लोग प्रभावित नहीं होते बल्कि विश्वभर में जो इसके श्रोता और दर्शक हैं, वे भी इसकी गुणवत्ता और इसकी प्रस्तुति से प्रभावित होते हैं। 38,000 कर्मचारियों वाला प्रसार भारती संगठन में इस समय 12,000 रिक्त स्थान हैं। इन 38,000 कर्मचारियों में 20 कर्मचारी संगठन काम कर रहे हैं। ये जो 20 कर्मचारी संगठन हैं, ये प्रसार भारती के काम-काज, इसकी गुणवत्ता और इसके चलन से इतने अधिक असंतुष्ट हैं कि ये कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि प्रसार भारती को भंग करके, उन्हें वापस आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में लौटा लिया जाए। इसको विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग माना गया था और 1978 में सबसे पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोचा कि एक स्वायत्तशासी प्रसारण निगम भारत में होना चाहिए, जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जो भारतीय दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो और उनको सूचना सामग्री प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय कल्याण और विकास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाओं का आदान-प्रदान, बहस, चर्चाओं तथा दृश्य और श्रव्य माध्यम से जो प्रस्तुतियां होती हैं, उनको उपलब्ध करा सके। इसके लिए एक बहुत उदात्त विचार के साथ यह सोचा गया था कि एक ऐसा स्वायत्तशासी प्रसारण निगम भारत में होना चाहिए, जो राष्ट्रीय प्रसारण का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा सके। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा जब यह विचार रखा गया था, तो उस समय आकाश भारती और इसके ऐसे ही कई अन्य नाम सामने आए थे और अंततः इसका नाम प्रसार भारती तय हुआ। अंततः 1990 में, जब श्री पी. उपेन्द्र सूचना प्रसारण मंत्री थे, यह एक्ट पास हुआ और सात साल बाद उस ऐक्ट को नोटिफाई किया गया। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की यह भावना लेकर जो प्रसार भारती प्रारम्भ हुआ, आज उसकी स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि वे कर्मचारियों को ही अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं। उनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर और भयंकर आरोप लगे। राष्ट्रमंडल खेलों के समय में शुंगलू समिति ने उन पर जो 135 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए, उन आरोपों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और इस कारण इसमें यह संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस की गई। महोदय, संशोधन लाकर आखिरकार क्या उपलब्धि होने वाली है? क्या आप केवल कर्मचारियों को दंडित करने, उन्हें सस्पेंड करने, डिस्मिस करने के लिए ही ये तमाम सरकारी, संसदीय कार्यवाही, विधायी कार्यवाही करेंगे अथवा उसकी गुणवत्ता

को सुधारने और जिस महान उद्देश्य को लेकर आडवाणी जी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रसार भारती को स्थापित किया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कोई विचार किया जाएगा? महोदय, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने प्रसार भारतीय की जो कथित स्वायत्त व्यवस्था है, उसके बारे में इतनी अधिक गलतियां और भ्रष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत किए कि जिसके कारण पूरे देश में प्रसार भारती का स्तर नीचे गिरा, उसकी साख नीचे गिरी। प्रसार भारती का उद्देश्य था कि वह सत्य को, शिव को, और सुंदर को दर्शकों के सामने रखेगी, लेकिन वह अंततः एक सरकारी पिटारा, 'बाबू भारती' बनकर रही। एक प्रकार से जो कार्य सरकार ने बी.एस.एन.एल. और एयर इंडिया के साथ किया, उनको वस्तुतः निष्प्रभावी बना दिया, वही काम प्रसार भारती के साथ हुआ। राष्ट्रीय प्रसारण की एक मुख्यधारा में शामिल होने की बजाय उसकी साख निरंतर नीचे गिरती गई और उसका प्रभाव, उसकी गुणवत्ता, निरंतर घटती गई है। जब यह ऐक्ट पारित किया गया था, उस समय यह कहा गया था कि यह निगम निरपेक्ष भाव से समस्त दर्शकों और भारतीय जनता के लिए ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेगा, जो उनके विवेक और राष्ट्रीय विकास के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लेकिन महोदय, आप इसके कार्यक्रम देख लीजिए, बॉर्डर क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा दूरदर्शन देखा जाता है, क्योंकि वहां पर बाकी प्रसारण ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर भी अक्सर यह शिकायत होती है कि यह केवल शहर केंद्रित कार्यक्रमों तक केंद्रित हो गया है और यह पूरे देश की एक पहचान, उसके चरित्र को प्रकट करने में पूरी तरह से असफल रहा है। महोदय, प्रसार भारती के संबंध में वास्तव में यह कहा जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल अथवा जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो इसकी गुणवत्ता, इसके कार्यक्रमों के बारे में वास्तविक योगदान दे सकते हैं, उनकी बजाय इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस अथवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आई.आई.एस. और आई.ए.एस. के अधिकारी लाए जाते हैं, वे किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं या उसको नया मार्ग दे सकते हैं? वास्तव में देखा जाता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो बजाय इसके कि लोग सरकारी या प्रसार भारती जैसे एक स्वतंत्र कहे जाने वाले चैनल को देखें, वे अन्य प्राइवेट चैनल्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी साख ज्यादा है और प्रसार भारती को साख केवल एक सरकारी विचार और सरकार के साथ जुड़े जो राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनको प्रकट करने तक ही यह सीमित रह गई है। महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक के माध्यम से हम कर्मचारियों को अनुशासित या दण्डित करने का अधिकार लेना चाहते हैं, तो उसके साथ ही कर्मचारियों के मध्य जो असंतोष है और आज प्रसार भारती में जो 12,000 रिक्ति स्थान हैं, उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। कहीं भी, एक शब्द भी ऐसा नहीं है, जो यह बता सके कि हम प्रसार भारती के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई विचार करने के लिए इच्छुक हैं।

अब मैं आपको घटनाएं बताता हूं। दूरदर्शन को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेज़ के प्रसारण का पूरी तरह से अधिकार था। Central Vigilance Commission के माध्यम से समाचार पत्रों में जो छपा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। "This is the case of the T20 Cricket World Cup matches, which Doordarshan did not telecast, despite having the rights to do it, through the Mandatory Sharing Act of 2007. This

abdication meant that ESPN could telecast them exclusively and make a tidy pie. This was after the ECSR said this should be telecast and also after obtaining a clear legal opinion affirming that T20 Cricket was to be considered a sporting event of national importance". करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। अधिकार था, अधिकार खरीदा हुआ था, उसको telecast किया जाना चाहिए था, किया जा सकता था, लेकिन किसी ने इस बात की जांच नहीं कि अगर यह telecast नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी थे, जिन्होंने एक भयंकर गलती और भ्रष्टाचार करते हुए भारत का इतना बड़ा नुकसान ही नहीं किया, बल्कि भारत की राष्ट्रीय प्रसारण संस्था की साख पूरी तरह से गिराई। इसी प्रकार CVC के अनुसार इसके लाभार्थी बताए गए हैं, "The beneficiaries of such generosity are NIMBUS, ESPN Star Sports, ESPN, Ten Sports, MSN, SET MAX, ICC and Big FM".

हमारे प्रसारण क्षेत्र के जो समीक्षक हैं और जो इस क्षेत्र को देखते हैं, वे प्रसार भारती के बारे में यह कहते हैं कि आज प्रसार भारती राष्ट्रीय प्रसारण का एक महत्वपूर्ण संस्थान न होकर जो निजी संस्थान हैं, चैनल्स हैं, उनकी मैत्री के साथ गिरता चला गया है। यहां तक कि प्रसार भारती के जो CEO बनाए गए थे, उन्होंने उसकी गुणवत्ता सुधारने और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऐसा काम किया कि कुछ ही दिनों के बाद वे रूपर्ट मर्डोक के साथ चले गए और उन्होंने प्रसार भारती को छोड़ दिया। यह तो प्रसार भारती का इतिहास है, जब कभी प्रसार भारती में गिरावट आई अथवा लोगों ने मांग की कि इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, तभी आप किसी IAS अफसर को ले आते हैं, किसी सरकारी बाबू को ले आते हैं। क्या प्रसार भारती के कामकाज की देखभाल करने या उसकी गुणवत्ता और कार्यक्रमों के बारे में जो एक पहचान होनी चाहिए, जो उसका योगदान होना चाहिए, वह कोई सरकारी अफ़सर केवल इस कारण से कर सकता है कि वह IAS या किसी दूसरी केंद्रीय सेवा से संबंधित है? हम इसमें क्यों नहीं प्रोफेशनल दर्जे के लोगों को नियुक्त कर पाते हैं, जो इसको वास्तविक रूप में निरपेक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने के लिए काम करें, न कि एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा का मात्र भोंपू बना कर छोड़ दें।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि the two member Committee headed by former Comptroller and Auditor General, Shri V.K. Shunglu, recommended action against the officer saying they cannot be rescued from the act of omission and commission which facilitated this wrong doing. 236 पेज की अंतरिम रिपोर्ट डाली गई। इस 236 पेज की अंतरिम रिपोर्ट पर, जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया और यह मान लिया गया कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। यह किस प्रकार का प्रयोग चल रहा है? एक ऐसा प्रयोग, जिसका देश के करोड़ों परिवारों के सदस्यों पर असर पड़ता है, जो ये कार्यक्रम देखते हैं। लेकिन कार्यक्रम देखने की दर्शकों की जो संख्या है, वह लगातार घटती चली

गई है। उसका समाचार ऐसा लगता है, मानो एक सरकारी प्रवक्ता PIB से उसकी एक प्रेस रिलीज जारी कर रहा हो। आप उसके विज्ञापन देखिए। उसके कार्यक्रमों के जो विज्ञापन होते हैं, वे इतने घटिया स्तर के होते हैं कि लगता है कि डीएवीपी के किसी बाबू द्वारा ही तैयार करके उनको चला दिया गया है। क्या इस प्रकार से हम 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' की भावना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं? क्या यह वही भावना है, जिसको लेकर प्रसार भारती की स्थापना की गई थी?

12,000 रिक्तियां हैं, जिनके कारण से प्रसार भारती के कामकाज में बहुत नुकसान, बहुत क्षति हो रही है। कोई भी कार्यक्रम ठीक से नहीं चल पा रहा है। आप प्रसार भारती के कार्यालय में जाकर देखिए, ऐसा लगता है कि आप किसी छोटे शहर के नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए हैं। कॉरिडोर में फाइलें पड़ी हैं, बाबू लोग इधर-उधर घूम रहे हैं, कही किसी का कोई नियन्त्रण नही है। वहां पर आने वाले कार्यक्रम के निदेशक या प्रस्ताव देने वाले लोग कार्यक्रमों के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, वे इतनी भयंकर हैं, जिसका उल्लेख करना भी कठिन जान पड़ता है। हर कार्यक्रम के पीछे कुछ न कुछ लेन-देन की बात होती है। हर कार्यक्रम के पीछे कुछ सिफारिशें होती हैं और इस प्रकार का आयोजन होता है जो उसकी साख पर बट्टा लगाने वाला होता है।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों प्रसार भारती के संस्थान में जितने भ्रष्टाचार के कारनामे हुए हैं, उनके कारण वहां के कर्मचारियों का मनोबल और गिरा है। उनको लगता है कि यदि वे वास्तविक रूप से काम करेंगे तो उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर वे कुछ श्रेष्ठ कार्यक्रम या अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि सारी चीज़ एक राजनीतिक चश्में से देखी जाती हैं। 'प्रसार भारती' को वास्तव में 'कांग्रेस ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन' में तब्दील कर दिया गया है।

सर, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वहां पर अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित किया जाता है। हमने स्वयं सिन्धु पर एक कार्यक्रम रखा था। मुनव्वर राना दुनिया के एक प्रसिद्ध शायर हैं, जो बहुत ही सैकुलर किस्म के शायर हैं। उन्होंने सिन्धु पर एक कविता लिखी थी-

जिस जगह से सिन्धु गुजरे समझो हिन्दुस्तान है।

यह वतन की शान है।

जब हमने उसे दूरदर्शन के प्रोजेक्ट पर डाला, तो हमें कहा गया कि यह कविता हम प्रसारित नहीं कर सकते। मुनव्वर राना ने समझाया कि सिन्धु हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है, यह पूरे भारतवर्ष की चेतना को अभिव्यक्त करती है। दुनिया में केवल भारतवर्ष ही ऐसा एक देश है, जिसका नाम वहां की एक नदी के नाम पर हिन्दुस्तान पड़ा, हिन्दू पड़ा। 'इंडिया' जो शब्द है, वह किसी ने दिया नहीं है, वह शब्द 'इंडस' से निकला है, 'सिन्धु' से निकला है। वह हमारी वास्तविक सांस्कृतिक चेतना और अधिष्ठान की एक प्रतीक नदी है, इसी कारण हम कह रहे हैं - 'जिस जगह से सिन्धु गुजरे समझो हिन्दुस्तान है', यानी वहां-वहां हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की

अभिव्यक्ति होती है। लेकिन वह प्रसारित नहीं की गई। चूंकि 'सिन्धु' से 'हिन्दू' की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए यह पंक्ति, जो मुनव्वर राना की ग़ज़ल थी, उन्होंने उसे प्रसारित करने से इनकार कर दिया।

महोदय, इसी प्रकार मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सीवीसी की रिपोर्ट पर एक टिप्पणी आई थी, "A few days later, on March 21st, all the nine Members of Prsaar Bharti found themselves being asked to sign another page of recommendation pertaining to the same meeting in which the order of candidates listed was changed to prioritize two officers for the post of DG, Doordarshan, over the name of another IBPS candidates." यह क्या खेल हो रहा है? कभी किसी दूसरी सर्विस के ऑफिसर को आप वहां नियुक्त करने के लिए खिलवाड़ करते हैं, कभी आप आईएएस को बुलाते हैं, कभी आप आईआरएस को बुलाते हैं। वहां के फाइनांस ऑफिसर और डीजी के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि उस झगड़े के कारण इस्तीफे लिए गए, अखबारों में उनके झगड़ों की खबरें छपीं। क्या ऐसे संस्थान के द्वारा हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह भारत की जनता को 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की भावना के अनुरूप कार्यक्रम प्रसारित करवाएगी या निर्मित होने देगी।

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि बीच में एक ऐसा समय भी आया, जब कांग्रेस ने 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' के चिन्ह को वहां से हटा दिया और उसमें से 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम् शब्द हटा दिया गया था। जब बाद में श्रीमती सुषमा स्वराज सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनीं तो उन्होंने वापस उसे स्थापित किया कि इसकी मूल भावना 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' ही है। यह वास्तव में भारतीय चेतना का एक उद्घोष माना गया।

महोदय, मैं आपको एक बात बहुत दुःख के साथ बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे यहां जनजातीय क्षेत्र हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं, लेकिन इनके बारे में प्रसार भारती में कोई विशेष योजना या कार्यक्रमों की कोई संकल्पना नहीं की जाती है। प्रसार भारती का पूरा संगठन निश्चित रूप से कुछ लोगों के विचारों को दबाने और कुछ लोगों के विचारों को बढ़ाने वाला हो गया है। जिस प्रकार से कल्पना की गई थी कि इससे सम्पूर्ण राष्ट्र की चेतना की अभिव्यक्ति होगी, देश के विभिन्न विचारधाराओं के लोग इसमें आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें अपने-अपने कार्यक्रमों तथा अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए एक समय और स्थान पा सकेंगे, ऐसा कुछ प्रसार भारती के माध्यम से नहीं किया गया।

महोदय, जिस प्रकार से यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, वह केवल कर्मचारियों को दण्ड देने पर केन्द्रित है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है और उसके जो कार्यक्रम हैं, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह संस्थान अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी दिशा में चल रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिए?

मैं इसी माध्यम से आपको परिवर्तन के कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले प्रसार भारती को पूर्णतः स्वायत्तशासी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। अभी एक कदम यह उठाया जा रहा है कि उसके

सी.ई.ओ. को भारत सरकार चुने ताकि वह उसके बारे में कार्रवाई भी कर सके। वास्तव में इसकी संकल्पना वैसी ही होनी चाहिए -- जैसी इलेक्शन कमीशन की एक स्वायत्त स्थिति है, वैसी ही स्वायत्त स्थिति प्रसार भारती की भी होनी चाहिए, ताकि उसके कर्मचारी स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकें और उसके अधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक कार्यक्रमों का निर्धारण कर सकें। एक श्रेष्ठ प्रसारण संस्था देश की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली संस्था हो तो उससे पूरे देश का गौरव बढ़ता है और भारतीय जनता को जो अपेक्षित है, वह भी उसे प्राप्त होता है। लेकिन, वह क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? वह इस कारण प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्यक्रम में एक राजनीतिक विचारधारा का चश्मा लगाने या उसमें एक रंग घोलने की कोशिश करते हैं और इसके कारण हमारे अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको बहुत कम महत्व मिलता है। उदाहरण के लिए जो हमारे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो सामान्य जनता रह रही है, उसके बारे में वहां कोई कार्यक्रम नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा म्यांमार से सटे हुए जो हमारे प्रदेश हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं तो प्रसार भारती के कार्यक्रम या तो बेहद उबाऊ और बासी किस्म के होते हैं या उनको देखना भी संभव नहीं हो पाता है और उनकी लोकप्रियता कहीं नहीं होती है।

महोदया, इसी प्रकार हम चुशूल गए थे। वहां 1962 की लड़ाई हुई थी। जब भारत के महान वीर मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों को परास्त करके 16 नवम्बर के दिन विजय प्राप्त की थी और उसको मरणोपरान्त महावीर चक्र दिया गया था। चूशूल के बारे में, वहां की जनता के बारे में और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जब हमने सुझाव दिये कि दूरदर्शन पर प्रसार भारती द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाने चाहिए तो उसका कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

महोदय, प्रसार भारती भारत के जन-जन को अभिव्यक्ति करने वाला एक संस्थान होना चाहिए। अगर वह केवल कुछ लोगों तक, कुछ वर्गों तक या कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहने वाला संस्थान बन जाता है तो अपने उद्देश्य का उल्लंघन करता है और वह वास्तव में एक redundant संस्थान कहा जाता है। उसके कर्मचारी जब हमें मिलते हैं तब कहते हैं कि जब कभी वे एक अच्छा कार्यक्रम लेने की कोशिश करते हैं तो उनसे यह पूछा जाता है कि क्या आप ऊपर से पूछकर आ गए? ऊपर से पूछने का मतलब यह होता है कि जो आई.एस.एस. ऑफिसर्स होते हैं, वे अपने राजनीतिक आकाओं से अनुमति लेकर यह बताएं कि यह कार्यक्रम किया जा सकता है या नहीं। कार्यक्रम की गुणवत्ता होनी चाहिए और कार्यक्रम का एक सम्प्रेषण होना चाहिए। क्या वह कार्यक्रम वास्तव में उस क्षेत्र को सम्प्रेषित करने में समर्थ है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए वह कार्यक्रम तैयार किया गया है? क्या वास्तव में भारतीय जनता की जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, उसके आक्रोश हैं, उसके असंतोष हैं या जो उसके disagreements अथवा असहमतियां हैं, उनको प्रकट करने में वह समर्थ है? जिस देश का National Broadcasting Corporation राष्ट्रीय

जनता की असहमतियों को प्रकट करने में संकोच करे, जिस देश की राष्ट्रीय प्रसारण संस्था उस देश की जनता की विभिन्न वेदनाओं और गुस्सा तथा सरकारी नीतियों के प्रति उनके मत में जो असहमति है, उनको प्रकट करने में संकोच करे, तो क्या हम उसको राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। वह किसी एक राजनीतिक विचारधारा का संस्थान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का संस्थान नहीं हो सकता। राष्ट्र का संस्थान वह हो सकता है, तो मातृभूमि पर अपने शीश चढ़ाने वाले देशभक्तों के बारे में भी सोचे, साथ ही उन लोगों के बारे में सोचे, जो गरीब हैं...। जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो लोग बेहद भुखमरी के शिकार होते हैं और उनकी आवाज अगर राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान पर नहीं आती, तो क्या वे चैनल्स उनको प्रसारित करेंगे, जो मार्केट driven हैं या जो पेड न्यूज के आरोप से ग्रसित होते हैं।

(उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए)

इस प्रकार के कार्यक्रमों की संकल्पना केवल राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान से ही की जा सकती है, क्योंकि वह जनता के राजस्व से चलता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि किसी पार्टी या किसी एक विशेष सरकारी संस्थान के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए, प्रसार भारती को संपूर्ण भारतवर्ष के प्रति उत्तरदायी बनाने वाला एक ऐसा संस्थान बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो पूरे क्षेत्र की भावनाओं को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह, बिना किसी वैचारिक अस्पृश्यता प्रकट कर सकें। आज प्रसार भारती संस्थान न केवल भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, बल्कि यह सबसे ज्यादा वैचारिक अस्पृश्यता का पालन करने वाला एक संस्थान बन गया है, जहां पर ideological apartheid पूरी तरह से प्रभावी होकर उनके कार्यक्रम, उनकी अभिव्यक्तियां तथा उनके प्रसारणों को निर्धारित करता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिले हैं कि किस प्रकार के समाचार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, किस पार्टी के समाचार, किसी संस्थान के समाचार, किस प्रकार के संगठनों के समाचार वहां पर आने चाहिए या नहीं चाहिए।

महोदय, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पिछले दिनों देश के एक प्रमुख महिला संगठन की महिला सदस्यों के दिल्ली में 14 जगह पर कार्यक्रम हुए। उन्होंने देश के युवाओं को, देश की युवा महिलाओं को लेकर उनको राष्ट्रीयता की भावना से संचालित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, देश पर मर-मिटने के लिए, सैनिकों की सहायता करने के लिए, राखी पर सैनिकों के पास जाकर उनको राखी बांधने के लिए और देशभक्ति की शिक्षा देने के लिए पूरी दिल्ली में कार्यक्रम किए, लेकिन दूरदर्शन पर वह कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ, बल्कि हुआ यह कि लंदन में जो बर्मिंघम पैलेस है, वहां की महारानी का जो पैलेस है, उसके बारे में उसी समय में एक कथा दी गई, एक समाचार दिया गया, लेकिन भारत की युवाओं का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसके बारे में समझा गया कि यह कार्यक्रम नहीं दिया जा सकता।

महोदय, इसी प्रकार गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में हुआ। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं generalise नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे ठोस उदाहरण हैं कि जब राष्ट्रीयता वाले लोग, विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, सेना के

क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने कार्यक्रम करते हैं, तो उनके कार्यक्रम दूरदर्शन पर या प्रसार भारती द्वारा अंगीकार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे किसी एक राजनीतिक रंग में रंगे नहीं होते। उस राजनीतिक रंग में नहीं रंगे होते, जिस राजनीतिक रंग की प्रसार भारती में मंडी हाउस में स्वीकारियता होती है, इसलिए वह स्वीकारिता रंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए, यह स्वीकार्यता वैचारिक भेदभाव के आधार पर नहीं होनी चाहिए, यह स्वीकार्यता केवल भारत और भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए। आप किसी भी रंग के हों, पंथ के हों, प्रांत के हों, भाषा के हों या किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, आप किसी भी बात को कहने वाले हों, आप चाहे सरकार के पक्ष में बोलें या सरकार के विपक्ष में बोलें, आपके हृदय की आवाज, एक हिन्दुस्तानी नागरिक की आवाज को अभिव्यक्त करने का संस्थान प्रसार भारती को होना चाहिए, वरना उसके नाम से स्वायत्तता जैसे शब्द हटा दिए जाने चाहिए और कह दिए जाना चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार आएगी, केवल उसी पार्टी की सरकार की बातों का यह प्रसारण करेगी और बाकी किसी विचारधारा का प्रसारण नहीं करेगी। क्या हम वास्तव में ऐसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र के प्रसारण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ हमारे सामने यह है कि हमारे रंग में रंगों, वरना हमारे विरोधी हो। हमारी बात को मानो, हमारे जैसे दिखो, हमार जैसे कहो, वरना हम तुम्हारी बात को सामने नहीं आने देना चाहेंगे। कहां गया वह मूल स्वप्न? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रसार भारती के संचालक आज पंडित नेहरू की बात करते हैं। पंडित नेहरू ने वैचारिक स्वतंत्रता के बारे में जो अच्छे शब्द कहे थे, क्या प्रसार भारती उनको मान रही है? पंडित नेहरू ने कहा था कि जिस देश में वैचारिक स्वतंत्रता का अर्थ यह माना जाता है कि मेरे विचारों से भिन्न व्यक्ति की बात को मैं प्रकट होने की स्वतंत्रता नहीं दूंगा, वहां पर वैचारिक स्वतंत्रता नही, बल्कि एक वैचारिक autocracy होती है। इसलिए आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इसीलिए प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी की बात उन्होंने कही कि जब तक आकाशवाणी से विभिन्न बातों को, हमारी जनका के दिल की बातों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बंदिश के प्रकट नहीं किया जाता, तब तक यह अपने नाम को सार्थक करने वाली संस्था नहीं कही जाएगी। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप और किसी की बात मानें न मानें, कम से कम पंडित नेहरू के विचारों को तो मान कर प्रसार भारती को वास्तव में स्वतंत्रा और स्वायत्तता दें। यह हिन्दुस्तान का सवाल है। यह किसी पार्टी या सरकार का सवाल नहीं है। आपको आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना होगा कि आपने किस प्रकार के संस्थान निर्मित किये कि पूरे देश की बात कहते थे या केवल मेरी पार्टी का और मेरा ठप्पा लगे हुए, मुहर लगे हुए कागजात को ही वे प्रसारित करने का अधिकार रखते थे। क्या आप इस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते हैं? हम लोग क्या इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर वैचारिक स्वतंत्रता हमारी पार्टी के रंग-रूप, चेहरे, शक्ल और मोहरे से निकल कर चलती हो और बाकी लोगों के साथ हम वैसा व्यवहार करें मानो वे अछूत हैं, अस्पृश्य हैं और हमारे साथ चलने के योग्य नहीं हैं?

महोदय, हम लोग अस्पृश्यता के विरुद्ध हैं। यदि हम सामाजिक अस्पृश्यता के विरोधी हैं, तो हम वैचारिक अस्पृश्यता के भी विरोधी हैं। हम उस विचारधारा को मानते हैं, जिस हिन्दुत्व की विचारधारा ने हिन्दुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र, बहुलतावादी समाज और संविधान की संरचना की। यह इसी बात का प्रताप रहा है कि हिन्दुस्तान दुनिया के सबसे महान लोकतंत्रों में गिना जाता है, जहां लाखों तरह की बातें और लाखों तरह की सुगंध एक साथ उठने की स्वतंत्रता है और किसी को यह नहीं कहा जाता है कि जब तक तुम मेरे रास्ते पर नहीं चलोगे, तब तक तुम संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। यह हिन्दुस्तान का सौंदर्य है, यही हिन्दुस्तान की शोभा है।

हमारे यहां कहा गया, "स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरण, पृथिव्यां सर्व मानवः।" यह वह देश है, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी-अपनी विद्या का अर्जन करके विश्व में नाम कमाते थे। यह कहा गया, "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।" हमारे पास दुनिया भर के विचार आएं। दुनिया भर के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हमारे पास आएं। हमारे यहां कभी किसी गैलीलियो को उसके विचारों के कारण सज़ा नहीं दी गयी। हमारे यहां चार्वाक को "षड्दर्शन" में ऋषि का पद दिया गया, भले ही चार्वाक ने वैदिक मत के विरुद्ध लिखा और कहा कि "यावत् जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत।" उन्होंने आत्मा को नहीं माना, उन्होंने वेदों को नहीं माना, उन्होंने वैदिक परम्पराओं के विरुद्ध लिखा, लेकिन हमने चार्वक को फाँसी नहीं दी। हमने चार्वक के बारे में यह नहीं कहा कि इसकी तमाम पुस्कतें जला दो, इसकी तमाम स्मृतियाँ खत्म कर दो, इसको कहीं प्रसारित मत होने दो, क्योंकि यह हमारी बात के विरुद्ध जाता है। महोदय, हमने चार्वक को "षड्दर्शन" में स्थान दिया।

आज मुझे दुःख होता है कि सत्ता पक्ष के सहयोगियों द्वारा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नियंत्रित लोकतंत्र की बात की जाती है। यह वही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है जो प्रसार भारती में अभिव्यक्त होती दिखती है। ये वही कंट्रोल्ड वैचारिक बंदिशें हैं, बंधन हैं, जो प्रसार भारती में अभिव्यक्त होते दिखते हैं। वे वही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का रूप है, जिसको ऑटोक्रेसी ही कहा जा सकता है। हमारे सत्ता पक्ष की ओर से यह सुझाव दिये जाते हैं कि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल कर लीजिए। आप उसमें Government का State में दखल डाल दीजिए। क्या इसे हम प्रसार भारती बनाने वाली सरकार का विचार कह सकते हैं? एक ओर आप कहते हैं कि हम प्रसार भारती बना कर स्वायत्तशासी, लोकतन्त्रवादी, स्वतंत्र, निरपेक्ष और सभी विचारों को अपने में अंगीकार करने वाली संस्था बनाएंगे, दूसरी ओर आप वैचारिक विरोधियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं और अपने से भिन्न विचार वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया को दबाने की जो बात हो रही है, यह वही मानसिकता है जिसने प्रसार भारती को एक पार्टी का प्रसारण-भोंपू बना कर रख दिया है न कि एक स्वायत्त स्वतंत्र संस्था। इसके लिए आवश्यक होगा कि न सिर्फ हम कर्मचारियों को अनुशासित करें और उसके संदर्भ में उसमें एक self mechanism निर्धारित करें। अगर

हम उसको सरकार के अंतर्गत एक कठोर और कंट्रोल्ड संस्था बना कर रख देंगे, तो प्रसार भारती का जो मूल उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा और वह वास्तव में अपने पुराने दिनों में चली जाएगी, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग-अलग थे। तब यह कहना होगा कि सरकार ने फिर से एक ऐसे महान उद्देश्य को लेकर स्थापित किये गये, स्वायत्त और स्वतंत्र उद्देश्य को लेकर स्थापित किये गये संस्थान को नष्ट कर दिया। महोदय, यह नहीं होना चाहिए। यह पार्टीगत राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर की बात है। यह सभी समुदायों के लिए बात है। यह सभी पार्टियों के लिए विचार की बात होनी चाहिए और सभी की सहमति से इस प्रकार की बात सामने आनी चाहिए कि प्रसार भारती हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की बात को प्रकट करने वाला संस्थान बने। चाहे वह व्यक्ति एक की minority में हो, चाहे वह व्यक्ति अकेला हो और उसके विरुद्ध ९९ लोग हों, तो भी उस व्यक्ति की बात को प्रसार भारती में उतने भी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रसारित करने का मौका मिलना चाहिए जैसे वह ९९ लोगों की बात को प्रसारित करती है। तब वह स्वायत्त कही जाएगी, तब वह स्वतंत्र कही जाएगी। इसी के साथ, जहां उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उस बारे में भी एक आत्म-निर्णय, एक self mechanism तैयार किया जाना चाहिए ताकि तमाम कलुष उस से दूर हों - वाणी का कलुष उस से दूर हो, कार्यक्रमों का कलुष उस से दूर हो, उसमें वैचारिक भेदभाव और अस्पृश्यता का कलुष उस से दूर हो, तब प्रसार भारती अपने वास्तविक धर्म का निर्वाह कर पाएगी। इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप दुनियाभर के उदाहरण देते हैं। आप को हिंदुस्तान की बातें कम अच्छी लगती हैं, विदेशों की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इस मानसिकता पर चोट करने के लिए प्रसार भारती की स्थापना की गयी थी, उस पर चोट कर के उसे सफल बनाना चाहिए। महोदय, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, "तेरे लब पे है इराको शामो मिस्र, रोमो चीं, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। अरे सब से पहले मर्द बन हिंदोस्तां के वास्ते, हिंद जाग उट्ठे तो फिर सारे जहां के वास्ते।" धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I stand here to support the Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010.

मेरे दोस्त श्री तरुण विजय, अगर आप के जमाने में दूरदर्शन ने कुछ miracle किए हों, आप के जमाने में उस ने कुछ अलग, independent जैसा रूप प्रकट किया हो, उसके एक-दो उदाहरण आप देते तो बहुत अच्छा होता। In fact, I stand here to support this Bill because at present there is no other alternative than to make certain amendments and somehow bring the Prasar Bharti on trakc. But, Madam Minister, as I told you sometime back also, eventually, I am of the firm opinion, I may be wrong, as experience shows, Prasar Bharti has to be wound up and entire power has to come to you, Madam Minister. You should

rule because there we have somehow failed. शायद वह नींव आप ने डाली, इसलिए वह हुआ होगा। आपने प्रसार भारतीय की नींव ठीक तरह से नहीं डाली। Sir, Section 12 of the main Prasar Bharati Broadcasting Act, 1990 lays down certain beautiful aims and objectives of the law. If you read the objectives and if you stare on the basis of this objective, the Prasar Bharti concept would not have failed. To that extent, the law enacted during that time was a good law but in the implementation of that legislation somehow we could not pull on. Therefore, today we are experiencing a very handicapped, ineffective Prasar Bharti. Sir, I have also my personal experience with Prasar Bharti, not that I have met any CEO much in the meantime. The personal experience is in the sense that Goa did not have a full-fledged studio for many years in spite of the fact that it was a laid down policy of the Government of India that in every State Capital there shall be a Doordarshan Studio.

But we had to be after him and ultimately somehow managed to have some studio. At that time Mr. Anand Sharma was the Minister. You can imagine a State like Goa where International Film Festivals take place. Till this date we do not have a news bulletin. Can anybody imagine that? We don't have a news bulletin. But Anand Sharmaji announced, when he inaugurated the studio, that very soon we will have a news bulletin in regional language. Announcement came. After six months, I put a question in the House as to what is the status of the news bulletin? Prasar Bharti is different and Ministry is different. A reply came from Prasar Bharti which was read out by the Minister. It said that there is no proposal before the Ministry to have a news bulletin. Can anybody imagine this type of an answer for which that CEO, against whom now cases are pending, that person was responsible. He was *, I would say a despot. He was not fit to be there as CEO.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please don't make such remarks. The word '*' is expunged.

SHRI SHANTARAM NAIK: I will show you the answer which is on record and I will show you Mr. Anand Sharma's speech. Then?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can't say like this.

SHRI SHANTARAM NAIK: Please understand these aspects. I will show the speech of the hon. Minister of Information and Broadcasting and the answer given here. These are two contradictory information. Somehow the Cabinet Minister gave the answer and...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't use the word *. You can say what you want. But, don't tell somebody who is not present here as *.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI SHANTARAM NAIK: Presently, the Ministry has no other option than to amend a law to bring in the employees on some sort of stable setup. But, Madam, deputation is for a short period. How long can we have such mass deputationists? For twenty years employees have suffered like anything. Employees of Doordarshan and AIR used to meet me. The condition was horrible, horrible in the sense they did not know where they are. Their status was not known, whether they are employees of Prasar Bharti or whether they are employees of Doordarshan or AIR? This situation was lingering for ten to fifteen years and then the employees had to go to court, spend lakhs of rupees on interpretation of deputationists, deemed deputationists, Government servants, and employees. There were lots of litigations. Lakhs of rupees were spent for fifteen years in the courts. Therefore, Madam, you have done the right thing to bring some sort of amendment to bring stability in this present scenario. Certainly, Madam, I would like to take some help. Goa is celebrating fifty years of independence on 19th December. In fact for the last six months, you may be aware and your officer may be aware, as to how I am after them to see that news bulletin at least is telecast on 19th December. Staff was not given for quite a long time. They were given one by one. These things went on. I would like to have firm assurance that there would not be any delay and that on 19th December, News Bulletin in regional language will be telecast on the Panaji Doordarshan. Secondly, Madam, as far as Doordarshan is concerned, Tarun Vijayji has said so many things, but I tell you, if today there is any channel which you can rely on, it is Doordarshan.

I don't say entertainment is bad. But what is happening in the country is shown only by the Doordarshan. That is the reliability; that is the credibility. Happenings in the nation are not shown at all. A film release becomes the title news, at the prime time, of private channels. This is the state of affairs of private channels. In such circumstances, the Doordarshan is doing a wonderful job. I remember, a discussion had taken place in this House. Shrimati Jaya Bachchan was then a Member of this House. Shri Shatrughan Sinha was also here. They both criticized the Doordarshan. I told them that if they were known in the entire country it was not because their films are released in theatres, but it is because Doordarshan telecast their movies to every nook and corner of the country. Theatres have got limitations. I asked them to accept this part. And, after that they corrected their stand. There is a feeling that we have no control over what has to be telecast and how

much control should be there. Everybody speaks of some sort of code. There is some code, some self-regulatory code. The Hon. Minister also sometimes says that she is helpless. But I am telling you that there is a concrete law in this country that lays down the programme code and the advertisement code. The Programme Code is laid down under rule 6 and 7.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): सर, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो सदस्य अब यहां नहीं हैं, वे केवल दूरदर्शन के कारण popular हुए। मैं समझता हूं कि यह तो 1985 के बाद टी.वी. को सब लोग जानने लगे। उसके पहले तो आकाशवाणी था। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के और अंतर्राष्ट्रीय नेता बने। उस समय तो टी.वी. नहीं था। तो आप यह मत कहिए कि केवल इसके कारण वे popular हुए। अपने व्यक्तित्व के कारण भी लोग popular हुए हैं। **...(व्यवधान)...** लेकिन ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि केवल उसके कारण वे हुए **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have got your point.

श्री विक्रम वर्मा: किसी मीटिंग में अगर कुछ बोला गया, तो ये उसको quote नहीं कर सकते। यह arrogance है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He was only referring to the debate that took place here. *...(Interruptions)...* Let me complete. *...(Interruptions)...* He did not criticize those Members. He was only referring to a debate. However, since you referred to it, I will go through the record.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, there is nothing to expunge from the record. The simple point is that when my hon. colleague says that Shri Shatrughan Sinha and Shrimati Jaya Bachchan got popularity only because the Doordarshan telecasted their movies, he is not right. Gandhiji became international leader without Doordarshan. Jawaharlal Nehru became Chacha Nehru without doordarshan. *...(Interruptions)...*

श्री विक्रम वर्मा: आप छोटा बना रहे हैं सामने वाले को।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Try to understand that. Don't misguide. Young people and everybody else is watching this. Don't give a wrong impression that you will become popular only when the Doordarshan will show your face on TV, and not with your good deeds. Tell the nation that good deeds will make you hero. *...(Interruptions)...*

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, rule 6, which contains some 10-15 items of code, is quite exhaustive. I will read only two or three codes from rule 6. I read, "No programme should be carried in the cable service which is likely to encourage or incite violence or contains anything against maintenance of law and order, which promote anti-national attitude... Criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of the country. Then, encourage superstition or blind belief. Then, against religious things, and women, all aspects are mentioned. Anybody may feel that this is a code of conduct, is a self-regulatory measure to be observed or not to be observed by the media. It is not so. I would like to emphasize that section 16 of the main Act lays down punishment up to two years if any provision of Programme Code or Advertisement Code or any other provision of law is violated. So, if anybody is under the impression that there is no law in this country and media can print and telecast anything it wants uncontrollably, then that is totally wrong. The other day, I was listening to a debate which was going on. Everybody was saying, "we are helpless". Nobody quoted the law that exists in the country. Besides, provisions of the Indian Penal Code are there. Maybe, they are archive bit, but they are there. Therefore, appropriate prosecution can be launched if printing material or any electronic material is defamatory or otherwise.

Then, we talk about Facebook or Twitter. Of course, we do not have that much of control over such international media. Nevertheless, kindly -- I request the hon. Members, some of them must be visiting -- go on Internet daily and read the Times of India website. There will be one item, say, political, social. Thereafter, below that, general public give their comments. I am not talking of Facebook, I am not talking of Twitter but I am talking of The Times of India. There, comments made about women are horrible. Suppose there is a lady who is politician. You will find horrible comments there but not related to the main news. Regarding your leader also I can mention something. With regard to Advani ji's yatra, somebody wrote: "I will shoot him when he enters my State." And that comment was allowed. There are also other things that I cannot even quote, but they are allowed. Everybody feels that there is no law to punish them.Every such comment is there on the Facebook or Twitter. I am giving these examples from the Times of India website. Please go through that Website at least once in three or four days. Click any news and see the comments below. You will find very horrible comments. Therefore, something has to be done. If an air crash takes place, what is the

comment. "I wish they will name all the leaders. " "I wish all of them were inside." Somebody writes. Again, I am picking up a sober comment. So, this is how they feel. Maybe, they may be writing from London or they might be writing from this country, but they are writing so. Today, Internet readership is increasing very fast. Lakhs and lakhs of people do Internet daily. Therefore, something has to be done in this regard. With these words, I support this Bill, but, ultimately, I repeat my request and then I agree with Vijay ji that you have to wind up Prasar Bharati and take the reins. Thank you.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal):Sir, we are not opposed to the Bill; we support the provisions of this Bill. Sir, the Bill seeks to settle the long-pending issues of the status of employees working in Prasar Bharati. Now, they will be treated as Government employees. To implement the provisions of this Bill, the management side is very important. That should be looked into to deal with the provisions of the Bill. Management should be improved. Sir, I would like to mention some of the recommendations of the Standing Committee. It said, "The Committee observe that the main cause of apprehension in the mind of the employees is the uncertainty about their recruitment regulations and service conditions. Had these regulations been finalized before bringing the legislation to Parliament, the concerns of the employees could have been addressed to some extent. The Committee place on record their unhappiness over the inaction on the part of Prasar Bharati in implementing the Prasar Bharati Act." That was the observation/remark of the Standing Committee.

As I am referring to the importance of the management side, to impress on the management side, I would like to quote here another recommendation of the Committee. It says, "The Committee strongly recommend that the concerns of the said category of employees about their promotional prospects should be taken care of." In another portion of its recommendations, they have said, "The employees associations should be assured about their promotional prospects through consultations before the Recruitment Rules and Service conditions of Prasar Bharati are notified and the amending provisions are put into operation."

Sir, the industrial relation is very important. The Standing Committee has also referred to this matter of seeking cooperation of the unions. But, presently, recognition of all the unions has been withdrawn and it has been withdrawn arbitrarily. When cooperation is necessary, the management

should be asked to deal with all the provisions of the Bill. Now without giving any reasons, the recognition of the employees' unions has been withdrawn arbitrarily. They are representing on it; but there are no talks with the Unions. So, I will request the Minister here to see the attitude of the management towards unions. The recognition of the unions should be restored back. Otherwise, its implementation will not be assured here.

Another point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is about the financial viability of the Prasar Bharati. About the financial viability of the Prasar Bharati, the Standing Committee has very categorically observed that the main reason for insecurity in the mind of officers and employees of Prasar Bharati is Government's own admission of Prasar Bharati being financially unviable before non other than the highest judicial body of the country, i.e., the Supreme Court of India." Many of the Members here also opined like that. So, I request that the financial viability of the Prasar Bharati should be looked into. The Committee strongly emphasized that Prasar Bharati should find out ways and means to mobilize funds to reduce dependence on Government's grants to meet the operational costs. That was the recommendation of the Committee.

Sir, to improve the financial unviable position, which needs to be taken into consideration, the management should be improved a lot and the recognition of all the unions should be restored. Otherwise, this provision cannot be put into effect. So, I request the Minister to look into the matter.

With these few words, I support the Bill.

प्रो. अनिल कुमार साहनी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने के लिए समय दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज दूरदर्शन, प्रसार भारती को गांव-गांव में, जहां पर केबल नहीं पहुंचा है, जहां पर अन्य समाचार चैनल, प्राईवेट समाचार चैनल नहीं पहुंचे हैं, वहां पर गरीब-गुरबा लोग दूरदर्शन को ही देखते हैं। हम लोग अपने बिहार में देखते हैं कि दूरदर्शन का प्रसारण ठीक प्रकार से नहीं होता है। आप वहां पर अपने प्रतिनिधि को प्रसारण देखने के लिए भेजिए। बिहार में इस प्रकार से आपका दूरदर्शन चलता है जैसे कि आंख खराब है। उस पर झिलमिल-झिलमिल चलती रहती है, वहां पर आपका प्रसारण ठीक से नहीं चल रहा है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। दूरदर्शन पर आपने जो समय सीमा दी है, वह बहुत कम है। अपने स्टेट को जो समय सीमा दी है, उसने 15 मिनट हिन्दी के समाचार के लिए और 15 मिनट उर्दू के समाचार के लिए है। मेरा अनुरोध है कि आपको समाचार के लिए समय सीमा

बढ़ानी चाहिए, ताकि जो राज्य द्वारा गरीब-गुरबा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनकी सही जानकारी उनको मिल सके। इस तरफ मैं मंत्री महोदया का ध्यान इस सभा के माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं। वहां पर आज, ई.टी.वी. बिहार के मुकाबले में आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपके पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको उस रिपोर्ट के अनुसार काम करने में क्या दिक्कत है? उसमें जो पैसा लगेगा, उसमें जो खर्च दिया जाएगा, उस खर्च में आप कटौती करते जा रहे हैं। प्रसार भारती के अंतर्गत उठने वाले कुछ बिंदु हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देशभर में प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी संवाददाता (पीटीसी) और दूरदर्शन संवाददाता (स्ट्रीन्गर) कार्य करते हैं। आकाशवाणी संवाददाता (पीटीसी) को प्रसार भारती की ओर से एक निश्चित राशि का पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है और दूरदर्शन संवाददाता (स्ट्रीन्गर) को समाचार प्रसारण की एवज में भुगतान किया जाता है, जबकि दोनों की योग्यता समान है। जब उनकी योग्यता एक समान है, तो दोनों को एक समान वेतन देने पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है? जो दूरदर्शन के नीचे के संवाददाता हैं, वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आपको दूरदर्शन मे जो नीचे का संवाददाता है, वह अपना पेट्रोल खर्च करता है और साइकिल से भी घूमता रहता है और आपके लिए न्यूज लेने के लिए जाता है, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जो निचले स्तर पर संवाददाता दूरदर्शन में समाचार प्रसारित करवाने के लिए जाता है, उसको आप उतना ही पारिश्रमिक दीजिए जितना कि आप आकाशवाणी के संवाददाता को देते हैं।

आकाशवाणी संवाददाता (पीटीसी) को आकाशवाणी में समाचार प्रसारण के साथ दूरदर्शन समाचार पर भी न्यूज फुटेज प्रसारण की एवज में अलग से भुगतान कर दिया जाता है। इससे दूरदर्शन स्ट्रीन्गर की रोजी-रोटी पर सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि इसे न्यूज फुटेज पर ही भुगतान किया जाता है जिसके कारण दूरदर्शन स्ट्रीन्गर की स्थिति बदतर है। जो लोग निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, आप उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जो निजी चैनल हैं, जैसे आज तक, जीटीवी इत्यादि हैं, उनकी रफ्तार में दूरदर्शन भी चलना चाहिए। दूरदर्शन को रफ्तार में चलाने के लिए, इसको जरूरत के हसाब से आगे बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि निचले स्तर पर प्रसार भारती को भी समय दीजिए। आप उसको भी समय दीज़िए कि वह लोकल समस्या को, लोकल आवश्यकता को न्यूज में उठा सके। आने वाले दिनों में दूरदर्शन द्वारा ही आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। आज इस देश में आतंकवादी, माओवादी समस्या है, इसको भी शांत करने के लिए आपका दूरदर्शन बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। अभी जिस प्रकार से आपकी पार्टी के एक साथी बोल रहे थे कि लोगों को जागृत करने के लिए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शुतुघ्न सिन्हा की फिल्म चलाते हैं, इस देश को बनाने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से जो आपका कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसको अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़कर, हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी समय देना चाहिए। आप सिर्फ

चुनाव के समय ही उनको चार मिनट या पांच मिनट का समय देते हैं। जो इनका विचार है, वह समय-समय पर प्रादेशित स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक देने का समय निकाला जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में दूरदर्शन और प्रसार भारतीय के माध्यम से इस देश को एक नया संदेश दिया जा सके। इससे देश एकजुट रहेगा, देश को मजबूती मिलेगी और देश में शांति बनी रहेगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने आप से मिलकर अर्ज़ की थी और एक पत्र भी दिया था मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। हमारा जिला मुजफ्फरपुर है और वहां के पत्रकार संतोष कुमार स्टींगर, दूरदर्शन सह अध्यक्ष ऑल इंडिया दूरदर्शन स्टींगर एसोसिएशन को प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन पटना से इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया था। उनसे रिश्वत भी मांगी गई थी। जबकि अभी भी इस प्रकार की खबरें लगातार राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होती रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रसार भारतीय में एक प्रकार से भाई भतीजावाद और अपने लोगों को भारती में शामिल करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी कुछ सांसदों ने कहा है कि इसको खत्म कर दिया जाए, तो मैं प्रसार भारती को खत्म करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो इसमें सुधार करने की बात कह रहा हूं। इसमें सुधार करने से देश को एक नया संदेश मिलेगा। आज प्रसार भारतीय में उसके स्टॉफ के साथ जो दोहरी नीति देखने को मिल रही है वह ठीक नहीं है।

महोदय, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा। यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसमें सुधार लाइए, ताकि इसके माध्यम से लोगों को और जागरूक बनाया जा सके और इसके माध्यम से सरकार का और विपक्ष का जो कार्यकलाप है, लोग उसको देख जायें। जय हिन्द, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shrimati Vasanthi Stanley; not present. Shri Pyarimohan Mohapatra.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Sir, at the outset, I would like to congratulate the Government, the Minister and the Prasar Bharati for two things. Doordarshan has been disseminating the culture, tradition and heritage of this country with diverse cultures and Doordarshan similarly is the main source of any authentic news, shorn of all tamasha or sensations. All India Radio similarly has been creating awareness of different beneficial programmes of Government among the rural masses. Having said this, I agree with my friend on this side that these two have been used as instruments or mouthpiece of the ruling party and the biased coverage that

takes place is indeed disgusting at times. I will not go further. I remember the case of an AIR correspondent, a very objective character, who never ever bothered about the ruling party or the opposition. He was very fair throughout. He was kicked around so much that he had to take voluntary retirement. He was in severe distress. I would advise every ruling party, anybody who comes to rule Delhi, please don't misuse Prasar Bharati. Have your own channel. Learn from DMK and AIADMK. They have their own channels. They air their parties' views through those channels and get enough coverage. Please have that. Let us not pollute institutions like Doordarshan and All India Radio which have a long history.

Then, regarding financial viability of Prasar Bharati, they have been funding somewhere around 45 to 48 per cent from their internal sources and the Government has been funding the rest. Can you not stop it? I am asking this because this is the road to subservience. The moment I am funded, I will certainly look at my masters and see as to what they want me to do. Why don't you allow them to improve their programmes? It is really distressing to see that there are some programmes of Doordarshan where they don't have any advertisements at all. There is not even a single advertisement. Last night, I was watching an entertainment programme, and there was not even a single advertisement. It is an electronic media and it cannot survive with this kind of programming. Allow them to do programming independently. Let them improve the quality. Let them go to the market. If necessary, let them have joint ventures with people who can really improve the space marketing in Doordarshan. I will mention only one or two things more. If you go through the Bill, if you look at the history, I can't understand how clumsy a Government can be. I am sorry, but there are officers, very senior officers, in this Ministry. There is no point in blaming the Ministers. And, why were all these officers not attacking the problem? You are not taking the bull by the horns. If the Prasar Bharati is to be created, why go with just some officers on deputation, then deemed deputation? Whose interest are you going to serve? Create an autonomous body. Once you talk of autonomy, see that all employees are under that organisation. If the Indian Information Service officers or the Central Secretariat Service officers want to serve there, let them get absorbed. If they don't want to get absorbed, let them get back. Then, there is GoM. Why do you need a Group of Ministers? What does the top bureaucracy do here? You look for a Group of Ministers to teach them, tell them as to what ought to be done. I thought it should have been the other way round. And, imagine, in 2010, commitments were made to the GoM that by such and such date, we will do this

about framing regulations. And, what did you do? Till today, this has not been done. You say that we have done so much; 88 out of so many recruitment rules have been framed. Is this the way? Why don't you tell that we will do this in two months' time or three months' time? Specific dates should be given.

Then, I would like to make the last but the most important point. This is the Parliament. You bring Bills. When you bring Bills, you go to the Cabinet. So many committees are there and then the Bill finally lands in the Cabinet. It means that every word that you are bringing in here, you are committed. Then, what happened? Suddenly, the Parliamentary Committee, which is there in the law, has gone; it is not implemented. Broadcasting Council is there in the law; but, it is not implemented. Why?

Have you got that liberty? Let us know because, Mr. Vice-Chairman, Sir, it is contempt of Parliament, if I can put it that way. It is recorded, 'shall have a Parliamentary Committee', 'shall have a Broadcasting Council'. The Government has no choice. Who are these people? It has to be investigated by this august House as to who are these people who, over the years, ever since the Act was notified, have chosen not to implement a vital part of the law. After bringing in a Bill before the House, and, after getting it passed by the House, it is not open to the Government to choose and say, I will implement this, or, I will not implement this. This House has put its stamp of authority on it, and, all you have to do is to carry it out even if you find the Parliamentary Committee inconvenient. And, why do you find the Parliamentary Committee inconvenient? You thought of it in the first place. You got it passed in this House. Are these the bureaucrats, who are finding the Parliamentary Committee inconvenient, or, is it politoracy? On this issue, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would suggest that a full investigation has to be made, otherwise, the executive can play with the laws passed by this august House. Thank you.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill, particularly, in view of the fact that this will settle long-standing issues of status of employees working in Prasar Bharati. But, at the same time, I share the views or the concerns expressed by some of the hon. Members that even after the verdict given by the Supreme Court as long back as in 2007, it took the Government four years to bring this Bill in this august House. This is something

unusual. However, keeping in mind that this will be beneficial for all those who are working in the Prasar Bharati, I support this Bill.

At the same time, I have certain points to make. Although these may not be related to the Bill in a sense but, in fact, we must discuss all these points. As all of us are aware, the Public Service Broadcaster plays a key role in the society, especially, in a thriving democracy but it must be a part of our civil society, independent of and distinct from the Government. The *Satyam Shivam Sundaram* idea, which one of the hon. Members was propagating from the very beginning of his speech, I share his views but until and unless this Public Service Broadcasters or Telecaster is distinct from the Government, that motto cannot be achieved. In fact, it should act as one of the bedrocks of society, and, seek to continuously enlarge the so-called 'public sphere'. It must play host to informed debates, provide space for alternative and dissenting view points, be a voice for the voiceless, and, give substance to the phrase 'participatory democracy' in which we are living.

The Public Service Broadcaster must be accountable directly to its owners, that is, the citizens of this country. It should be self-sufficient in all respects, and, must not depend on the Government funding only. There should be multi-channel strategy for the centralization of Prasar Bharati. Each channel, whether it is *Doordarshan or Akashwani,* should have a defined clear identity for a specific set of viewers. For example, compared to private channels, the programmes of *Doordarshan or Akashwani,* though rich in content and substance, and, educative too, to a great extent, the entertainment programmes have not yet come up to expectations of a large number of viewers, particularly, the younger generation. Sir, you may remember Hum Log serial. It was introduced by Dada Muni (Ashok Kumar) whose birth centenary we are observing this year. There are many other serials which we used to watch on Doordarshan a few decades back. Now such type of serials and programmes are absent. This part should be looked into. The Human Resource Policy of the Prasar Bharati also needs to be strengthened to such an extent that innovative programmes could be conceived and introduced to satisfy the younger generation. Although many technologies have since been introduced, the Prasar Bharati must strive for more and more popular programmes. It must not act like another department of the Government.

Finally, I would like to say that our great culture, heritage, and niceties of our pluralistic society

should be the guiding factor for the Prasar Bharati in days to come. ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि लोग दूरदर्शन को दूर से देखें, निकट से न देखें। This is my humble submission. With these words, I, once again, support this Bill.

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से 'प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010' का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। एक कहावत है, 'देर आए दुरुस्त आए', आपने भी इस विधेयक को लाने में काफी समय लगा दिया। इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, वे बड़ी अनिश्चितता में थे, मुझे ऐसा विश्वास है कि अब उनकी वह अनिश्चितता दूर होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों ने भारतीय प्रसारण निगम के बारे में एक धारणा भी बनाई थी कि इसकी वित्तीय स्थिति दयनीय है, इसलिए इनको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए ताकि देश के कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि भारतीय प्रसारण निगम की स्थिति बहुत सुदृढ़ है और ठीक है। इससे हट कर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक विश्वसनीयता होती है। आज हमारे जितने भी साथी बोले, कहीं-कहीं यह पुट दिखा कि आपका दूरदर्शन केवल एक सरकारी चैनल बन कर रह गया है, सरकार चाहे किसी की भी हो। इस धारणा को बदलना होगा। निश्चित रूप से आप भी कम्पटीशन में हैं। दूरदर्शन कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, जब प्राइवेट सैक्टर आ जाता है, तो स्थिति बदल जाती है। दो चीजों में प्राइवेट सैक्टर ने बड़े जोर-शोर से काम किया है - एक तो दूरदर्शन में इतने चैनल आए, दूसरा टेलीफोन में इतनी कम्पनियां आईं। आपका जो सरकारी मंत्रालय हैं, जो सरकारी तन्त्र है, वह कम्पटीशन में कहीं न कहीं पीछे रह गया है। मंत्रालय और सरकार देश की संस्कृति है, देश की सभ्यता है।

आप चैनल देखते हैं, सभी साथी देखते होंगे, चैनलों पर जिस तरह से खराब दृश्य दिखाये जाते हैं, आखिरकार उन पर भी कोई कंट्रोल होगा या नहीं होगा? अच्छे आदमी को एक दिन में विलेन बना देना, विलेन को एक दिन में देवता बना देना, बढ़िया आन्दोलन को एक दिन में फेल कर देना और खराब आन्दोलन को एक ही दिन में सफल कर देना। किसी पर कोई मुकद्मा हो, अदालत उस पर कोई फैसला दे पाए या नहीं दे पाए, पुलिस चार्जशीट दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन ये चैनल चार्जशीट भी लगा देते हैं और उसमें सजा भी दिलवा देते हैं कि इसमें इतने साल की सजा होती है। आखिर इस पर कंट्रोल कहां से होगा? आप लोगों को इस पर भी एक विधेयक शीघ्र लाना पड़ेगा। आप यह जो विधेयक लाए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको एक विधेयक और लाना पड़ेगा तथा इन पर नकेल कसनी पड़ेगी।

अभी हमारे एक साथी ट्विटर और फेसबुल के बारे में कह रहे थे। अगर वे उस पर अपनी कोई भावना लिखते हैं और वह उनके तथा उनके साथी तक ही रहे, तब तो वह प्रसारण में नहीं आता है, लेकिन अगर वह सार्वजनिक हो जाता है तो वह भी आपके नियम के अन्तर्गत आना चाहिए। वह कैसे नहीं आएगा? वे किसी के बारे में कुछ भी

लिख देंगे! मैं समझता हूं कि इस मामले में यह सदन आपके साथ है। आपको इस तरह का एक विधेयक शीघ्र ही लाना पड़ेगा वरना ये लोग देश में जिस तरह की भ्रांति पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से दूरदर्शन का दुरुपयोग -- अब या तो competition इतना ज्यादा आ गया हो कि वे सही आदमी को विलेन साबित करें और हम उसे सही साबित कर दें। इसलिए, या तो हम competition में उनके बराबर हों अथवा देश में विश्वसनीयता आ जाए। जैसे, एक समय था, जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तब बी.बी.सी. लंदन से जो खबर आती थी, उसे ही सही माना जाता था। आज आप उस बी.बी.सी. लंदन वाली विश्वसनीयता कायम कीजिए कि दूरदर्शन पर जो खबर आएगी वही सही होगी, बाकी तो कहीं-न-कहीं से प्रभावित हो सकते हैं, मगर दूरदर्शन किसी से प्रभावित नहीं होगा। यह विश्वसनीयता देश में आनी चाहिए। अगर आप इन झूठी खबरों, अश्लील खबरों, अश्लील चित्रों और अश्लील बातों को देश से खत्म नहीं करेंगे तो इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता को ये लोग सारा-का-सारा मिटा कर रख देंगे। यह मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं।

सर, मेरे इतने ही सुझाव थे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A.W. RABI BERNARD (Tamil Nadu): Sir, I rise to express my views and concerns on the Prasar Bharati Amendment Bill, 2010. This Bill reminds me of the ways the Lord works in every individual's life. Twenty years ago, in UPSC Office in Delhi, I attended an interview and I passed that examination to be an Officer in Prasar Bharati or All India Radio or Doordarshan. Thinking back after twenty years, here I am expressing my views in this august House of Parliament. In my interview, the interviewer asked me that having come from abroad after long years of work and study, why I wanted to work in a Government organisation with a starting salary of Rs.2200. I distinctly remember it was Sikh gentleman who asked me this. I told him that if I join a private organisation, a private television company, I may be selling toothpaste; but, by joining a Government organisation, All India Radio or Doordarshan, I would sell the habit of brushing teeth and contribute to the development of the nation. I was selected, maybe, because of this reply. I was selected but I did not take up the job. I do not know why. But, my sister had taken up the job. Both of us were selected. It is in the similar spirit of mind that 36000 human beings, people, employees are working in All India Radio and Doordarshan and this Bill concerns those 36000 people. I request the hon. Minister to handle those people carefully. You are handling 36000 human beings. One of the concerns of these 36000 human beings is stagnation and more than 800 Programme Executives of All India Radio and Doordarshan have

been stagnating without even a single promotion in their career for over 30 years. These are people who are highly talented. After a post-graduation, after several years of experience they are selected. After writing the UPSC examination they are selected. But they are kept in one job for 30 years without any promotion, without any growth. On the other side so many Doordarshan Kendras, All India Radio stations remain headless, directionless and remain in a state of coma. Consider promotions for these creative people. You have an excellent library, terrestrial broadcasting is your monopoly. You handle 36,000 people, the largest public broadcasting corporation of the world. You are getting enormous support from the Government of India through subsidies, salaries and other facilities. Make use of these extraordinary opportunities. Train these people. You are talking about 36,000 people coming into the fold of the Prasar Bharati. The Bill elaborately says why these 36,000 people are being transferred from Government service to the Prasar Bharati Service. It has been said that this will enable the Prasar Bharati to control them, to transfer them from one job to another, to transfer them from one place to another. Think of differently. Think from their point of view. Make this as a window of opportunity to train these people, to make use of their potential, to make use of their talent and help them generously so that they will contribute without any hesitation with all their creative talents for the development of this largest company.

There is another category of people, thousands of them. They are called producers. Initially they were recruited as casuals on a contract basis for specific works. Since they were recruited on a contract basis for specific work, they are not being promoted, they can not even demand promotion. At least, the Programme Executives can demand promotions. The producers are not even able to demand promotions. Take care of them. Take care of their concerns. Many All India Radio stations and Doordarshan Kendras remain headless. They are direction less. At least, from now on fill up all vacancies in all Kendras.

Finally, I have a suggestion. Since broadcasting is a Central Government subject. I request the Minister, this Government, to consider providing time slots to the State Governments, at least, two hours a day so that you will not be blamed for being manipulative of this huge organization. You can give a sense of participation to the State Government. This happens in other countries. This happens through PBS in America, KBP in Philippines and in many other countries. Think of giving, at least,

two hours a day to the State Governments. You will get creative talent. You will get excellent programmes. The culture of the State will be reflected. Thank you very much.

SHRI M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010 on behalf of our party. At the same time, I take this opportunity to bring it to the notice of the august House one or two issues because there is no time also for me. If you recall, the Prasar Bharati was created for the sake of autonomy. But this autonomy was absolutely misused by the head of the people for their personal use and for their personal benefit by spending huge public amount. It is not at all useful for the Organization. As our friend has rightly pointed out, there is a talent also, but this talent was not utilised by the Heads. I will cite one example. In recent games, CW Games, telecast was outsourced to SAIs. But they got the benefit of at least Rs.100 crores as per the Committee Report. If they themselves had utilised that, they would have created an infrastructure of highest quality just like Asian Games where quality was introduced. The average age here also is 50 years whereas the private channels have 25 years. How can they compete with the private channels professionally also to telecast good programmes? I am demanding from the hon. Minister that at least one programme be organised for name and fame for this Institution, Prasar Bharati. I will be very happy. Anyhow, long contentious issues of this Service problems by passing this Bill will be solved. With the fond hope, that this Organization will compete with BBC in projecting India, with that hope only, I am supporting this Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Reddy. Shrimati Vasanthi Stanley.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. I would like to congratulate the Government on having introduced this comprehensive and straightforward Bill. It is commendable that it has initiated measures to especially address the long-standing concerns that Prasar Bharati employees have had about their employment status.

This Bill is coherent and unambiguous about (a) the status of Prasar Bharati employees and (b) the control, disciplinary and supervisory powers accorded Prasar Bharati on its employees, including the power to transfer them from one place, post or media to another.

The amendments envisaged are also commendable. In particular, the Bill amends Section 11 and includes (1) the officers and employees recruited in Akashvani or Doordarshan who were in service as of 1st April, 2000, who would be on deemed deputation to the Corporation with effect from the 1st day of April, 2000, and shall so continue till their retirement; (2) the officers and employees recruited during the period on or after the appointed day till the 5th of October, 2007, would be on deemed deputation to the Corporation with effect from the 1st day of April, 2000 or the date of their joining service in the Corporation, whichever is later.

At this juncture, I would also like to emphasise the recommendations of the Standing Committee on the issue of ensuring that the employees on deemed deputation should be considered senior to Prasar Bharati employees, and it would not affect their promotional prospects also. The promotional prospects of employees have also been given consideration in this Bill. Recruitment rights and service conditions have been made clear.

Sir, the other Members have, in detail, discussed this Bill. At this juncture, Sir, I would like to take this opportunity to share my few concerns about the small screen sector. The Government-sponsored medias, Akashvani and Doordarshan, are not commercially viable. But, definitely, the programmes are standard, educative and, to an extent, we can afford to sit and watch them with our families and children. But at our fingertips, we are able to get all the channels working in the world.

It is quite apparent that the media has done the role of a Judge by passing judgments, and being biased in its views, Media today exaggerates certain events and, in the process, does not fully appreciate others which are equally significant. Take the example of our Sharad Pawarji. He was assaulted once. But since it was repeatedly shown by them, the whole party, the people of his party, had to go on a strike and resort to other things. We do condemn both, the media who is exaggerating it, and the person who has attacked him also.

Sir, we witnessed a milestone when the Rajya Sabha was able to impeach a sitting Judge in the last Session. But due to the unnecessary uproar caused by the media on the Anna Hazare movement, it was not at all noticed. I appreciate Anna's initiative to improve the governance. But, at the same time, the media has not focused on other important issues. I would like to recall the Mumbai blast issue, on this occasion, when the media was repeatedly showing the attack; whereas,

the Mumbai people started attending their routine work long back. But the repeated showing of the same attack by the media was only instilling fear in the minds of people.

I would now like to take up the 2G issue. Till now, nobody is able to arrive at the real loss of revenue in this case. But whoever has set the fire, we have lost the roof. Media frame the charges, conduct the trials and are themselves giving the judgement. Everybody enjoys until the fire touches them and burns them. I would like to know: who is going to tie the bell to the media? In this august House, we are supposed to discuss all matters. We are having restrictions saying that certain matters are sub judice and all that, but the same matters are being discussed in detail in the media by the same people who are also representing the courts. Take for example, Shri Vijay Agraval, who is representing some cases or Shri Ram Jethmalaniji, who is also representing different cases. The same cases are being discussed in the media; whereas, we are restricted to discuss those cases by saying that they are *sub judice*. I would like to know whether the Government would take steps to put an end to the media discussing matters which are *sub judice;* otherwise, we should also be allowed to discuss those matters in this august House.

Last but not the least, the way in which ladies are being depicted on the small screen, I am really very much worried. There are two main ladies who are being shown in serials repeatedly. One lady is always crying. She sacrifices everything and she is the scapegoat of the whole family; otherwise, she is Machiavellian type of lady. Are they not able to see normal ladies in real life?

What about some advertisements? A man is having in his hands a body spray and all the ladies are going after him. One lady is not noticed by her boy friend because she is dark. After she applies some fairness cream for one week, she becomes bright and then all the boys are after her. Why? Shame! The hon. Minister, Shrimati Ambika Soni is sitting here. We have to have a regulatory system like the Censor Board. I have represented the State Censor Board. So far as the big screen is concerned, we have the Censor Board system, we have the regulatory system. But why is it not there for the small screen? All that is banned on the big screen, is being shown in detail on the small screen. We should have a regulatory system. I would request the Government, through this august House, to, at least, wake up now and take this opportunity to do something in this regard. With these observations, I welcome this Bill.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill that has been brought before this House by the hon. Minister of Information and Broadcasting. I also rise to lend my support to the suggestion made by Shri Shantaram Naik. In doing so, I would like to draw your attention to certain dates that have been mentioned along with the Bill that has been presented to us. This Bill was passed in 1990 when the Congress was in the Opposition Benches. I am a creature of that time. I remember the canard of Doordarshan being called Rajiv Darshan, which these people were going to correct by setting up Prasar Bharati as an independent authority that would ensure that the public broadcasting service would not be used for partisan purposes. Fortunately, two Governments fell in quick succession, in 1990 and early 1991, owing to their utter incompetence. And we were, therefore, able to put this silly idea of Prasar Bharati on the backburner until *alas* we lost in 1996. Then, there was a series of Governments. We first had Deve Gowdaji. Then, we had I.K. Gujralji. Then, we had Vajpayee-I; then, we had Vajpayee-II; then, we had Vajpayee-III. Between 1997, which is the date given in the Bill, and 2004 when the Congress was again in the Opposition Benches, this institution, Prasar Bharti, was established by the gurus of Shri Tarun Vijay who fell upon us like the Assyrians falling like a wolf upon the fold. Everything that is wrong with Prasar Bharati is the consequence of its having been conceived of by non-Congress elements and its having been implemented by non-Congress Governments. It is a useless organisation which is not surprising considering who set it up and why it was set up.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): I think you have got your facts wrong. In 1997, Tarun Vijay or people associated with him had nothing to do with the Government. It was a Government supported by your Party. So, you are re-writing history!

SHRI MANI SHANKER AIYAR: But we were still on the Opposition Benches.

SHRI ARUN JAITLEY: But you supported the Bill. You were on the supporting Benches. Jaipal Reddy as the I&B Minister brought the Bill. The Government of the United Front was supported by your Party. Please, do not re-write history.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Okay. Sorry. Carry on. Please make my speech.

Mr. Vice-Chairman, Sir, Shri Jaipal Reddy, unlike some of his colleagues in that Government,

has grown up; he has discovered that wisdom lies on our side. As for Shri Tarun Vijay, I was referring to the speech he made just now, wherein he was blaming the Congress...

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Just a minute, Sir. Sir, he has been saying that this Prasar Bharati is the child of the Government 'when we were in the opposition'. Now, he has to correct himself and get his remarks expunged because his whole argument is based on a wrong premise. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Sit down please.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, my premises are drawn from the document before us. The document before us tells us that the Bill was passed in 1990 when the Congress was in the opposition. In 1997, this institution started being set up and between 1997 and 2004, a period of seven years during which this grew from a tadpole into a frog, the Congress was not running the Government.

I am only pointing out that what Shrimati Ambika Soni has attempted to do today is to rectify all the errors, particularly the errors with respect to the ordinary lives of ordinary people working in Prasar Bharati which had been completely jeopardised by an ill-thought-out organisation which was badly run. Unfortunately, the size of the problem that the Government of India inherited on the 22nd of May, 2004 was complicated by the fact that dissatisfied employees had in large numbers gone to various courts and, therefore, there had to be a pause while the courts considered matters which were *sub judice* and it was after the fact that there was a court pronouncement in the year 2006 that a Group of Ministers was formed. It was my privilege to be a member of that Group of Ministers. And it is my privilege today not being a Minister of any kind to be able to give vent to the totality of my views on this subject.

Number one, what has been proposed in this Bill is an extraordinarily effective course correction. These people who were misled into going into Prasar Bharati and, then, Prasar Bharati itself remained non-functional for several years and when it did become operational, it became dysfunctional from being non-functional.

And, then, covered itself truly in glory in connection with the Commonwealth Games when we discovered just what a corrupt organisation it could be! This Bill aims at rescuing innocent Government servants who had been misled by the high ideals presented at the time of the creation of Prasar Bharati, who thought, as Rabi Bernard thought, that he was going into a noble profession and discovered to their cost that there was no noble profession; all that was involved was serving a supernumerary organisation. Why is it supernumerary? At the time the Prasar Bharati was conceived, there was only one television channel in India, that was the Government's Doordarshan. As a result of certain farsighted moves that had been taken even in the 1980s, from about 1990 we started getting into the system a huge number of private channels, many of them local to particular regions, others specific to their languages, and yet others which were of an international character.

Today, there is absolutely no shortage of competing television channels as well as competition on the airwave. In these circumstances, the reason why Prasar Bharati was thought of as an organisation being independent and, therefore, able to subvert directions of the Ministry of Information and Broadcasting, that error has gone; it is gone because right from 1990s and into the 21st Century, we have a large number of these channels competing with each other and dealing with information, entertainment and communication in the manner in which the private sector is prone to do, which is to function like a bumble bee; they are completely superficial; they are completely trivial; and most of them put me on as well, so I am part of this exercise. But, there is no consistency in either sticking with the subject or analyzing it in depth, or arriving at a considered solution. Eight people are put on a screen and the screaming hysterical anchor full of prejudices in his mind — I am particularly thinking of one person; he then gives eight people about half-a-minute in which to express their views; even in that half-a-minute, if they express a view that is different to his own, he shuts them off! Yes, it is entertaining. Yes, it is a great fun. Yes, there is some amusement to be had from all this. But, to suggest that this is all that we need for a developing country, in a democracy, is to completely underestimate the importance of the communication waves.

Therefore, I believe that now has come the time when given the fact that there are plenty of private channels, the Government should use its monopoly of the terrestrial system which reaches all those who do not get the satellite system. Those who have the satellite systems can spend the days looking at the *saas bahu* serials and the evenings looking at these anchors screaming at the

audience. But, those who do not have access to this satellite system are the ones who are looking at the television that comes through the terrestrial.

My plea with you, the hon. Minister, is that Doordarshan should be converted into a really effective public broadcasting system. It should have top professionals. It should pay absolutely the top rank. It should function like BBC does. There was one hon. gentleman who was objecting to the Government giving money to Doordarshan. But, the fact of the matter is that BBC has been funded by the British Government for ages. That BBC has made a worldwide reputation for being objective, for being in depth, for being persuasive and for being able to cross barriers which dictators attempt to raise.

In these circumstances, it is essential that Doordarshan has its own USP. Prepare a charter for yourself, Madam Minister, ensure that once you have established this charter and given it to Doordarshan and All-India Radio, then there is no ministerial interference. Let them run the show; let them run it professionally; let them run it with deep pockets; let them go around and collect advertisements, but not become staves to the advertisers as almost all our private sector channels are. And let us try and get out more substantive nation building messages through All India Radio and through Doordarshan, through the terrestrial route to the large number of Indians who do not have access to satellite. ...*(Time-bell rings)*... Yes, I am just concluding. It is in the light of this that I would request you to seriously end the Jurassic Park situation in which you have both Doordarshan as well as the Prasar Bharati. It is a needless administrative inconvenience. Just get rid of Prasar Bharati. Simultaneously prepare a charter, which will really give independence to Doordarshan, make it a truly serious and a truly national channel.

Let it be run by professionals, and let us, perhaps, work towards abolishing the Ministry of Information and Broadcasting because the Ministry of Information and Broadcasting is a colonial or war construct. Any advanced democracy does not have this Ministry. So, we will have to keep you there until you abolish the rest. But let us get to the stage where we have Doordarshan functioning as a genuine public service broadcaster, and, then, we will take on these wretched private channels who are slaves to the capitalists who are funding them, and, then, we will see genuinely that this

country has a choice between the trivia presented by our private channels, and the depth to which a public sector service can go. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Mani Shankar Aiyar.

Now, hon. Members, the hon. Finance Minister is here. He has to go to the other House. Therefore, if you all agree, the House agrees, I will have a break here now. The hon. Finance Minister will reply. And after the reply is over, we will continue the discussion, and the Information and Broadcasting Minister will reply to the debate today itself. Do you agree?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Okay, go ahead.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, Mr. Finance Minister.

SHORT DURATION DISCUSSION

The situation arising out of unprecedented rise in prices of food and other essential commodities and its effects on common man

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. First of all, Sir, I would like to express my gratitude to all the hon. Members who have participated in the discussion on my Statement which was laid on the Table of this House on 23rd of last month, the second day of the Winter Session, in the context of the Resolution which was adopted by both the Houses in August, 2011, asking the Government to take effective steps to contain the inflationary pressure. I would also like to express my thanks to the entire House, through you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for accommodating me to reply to the debate, by interrupting the discussion on another important issue which this House has taken up. As the same subject is being discussed right now on the floor of Lok Sabha also and I shall have to there, and, thereafter, reply to the debate. For this accommodation, I express my deep gratitude to the Members of this august House.

Sir, first of all, I would like to say that it is true we have discussed the issue of inflation a number of times, but as the same inflationary pressure still continuing on the economy. There are various factors but the major economic factor is the mismatch between demand and supply which is